भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 106
गुरूवार, 20 जुलाई, 2023/29 आषाढ़, 1945 (शक)

सृजित की गई नई नौकरियों की संख्या मापने की पद्धति

106. डा. अमर पटनायक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा 23 जून, 2023 को मंत्रालय के प्रदर्शन के संबंध में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वर्ष 2014 से सृजित की गई 12.5 मिलियन नई नौकरियों के किए गए दावे के अनुसार सरकार ने नौकरियों के इन आंकड़ों के मापन और उनकी संख्या निर्धारित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी नौकरियां सृजित हुई है, तत्संबंधी क्षेत्र-वार तथा उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की गुणवत्ता और संधारणीयता का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन या मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2014-15 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 15.84 करोड़ थी जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 27.73 करोड़ हो गई है। इसके साथ-साथ, पेंशनभोगियों की संख्या भी वर्ष 2014-15 में 51.04 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 72.73 लाख हो गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सितंबर, 2017 से अपना मासिक पे-रोल डेटा प्रकाशित कर रहा है जिससे औपचारिक क्षेत्र में रोजगारों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। देश में ईपीएफ अंशधारकों में निवल वृद्धि, वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 122.3 लाख और वर्ष 2022-23 के दौरान 138.5 लाख थी।

श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) से क्रमबद्ध तिमाहियों में, भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों के संबंध में रोजगार की स्थिति का आकलन किया जाता है। यह चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और वित्तीय सेवाएं हैं। क्यूईएस (जनवरी-मार्च, 2022) से यह

जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था के इन नौ क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 3.18 करोड़ हो गया, जबकि छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) के अनुसार इन क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ था।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), वर्ष 2017-18 से, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र करता है। पीएलएफएस, नौकरियों की गुणवत्ता और इसकी स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए रोजगार की स्थिति, काम के घंटे, प्रति घंटा आय, काम के अतिरिक्त घंटे, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त श्रमिकों की संख्या, भुगतान की गई छुट्टियां, लिखित नौकरी अनुबंध आदि पर आंकड़े भी एकत्र करता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान, सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों का व्यापक उद्योग-वार अनुमानित प्रतिशत वितरण अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

राज्य सभा के दिनांक 20.07.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों का व्यापक उद्योग-वार अनुमानित वितरण (% में)।

क्र. सं.	एनआईसी-2008 के अनुसार व्यापक उद्योग-वार	**2021-22**
1	कृषि	45.5
2	खनन एवं उत्खनन	0.3
3	विनिर्माण	11.6
4	बिजली, पानी, आदि.	0.6
5	निर्माण	12.4
6	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	12.1
7	परिवहन, भंडारण एवं संचार	5.6
8	अन्य सेवाएं	11.9
	कुल	**100**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई